राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

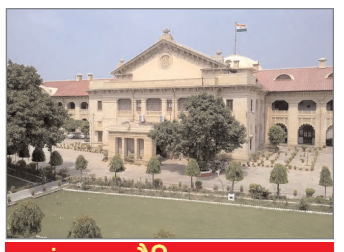

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, मंगलवार , 30 जून 2026
वर्ष 14, अंक 82, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया
www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

तालाब में 30 कुंतल मछलियां मरीं,मत्स्य पालक को लाखों का नुकसान..03

पुणे मंगेतर मर्डर केसः सिया-चेतन ने अपने 3 साल के प्लान के लिए ले ली केतन अग्रवाल की जान!...04

बिहार में जमाबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट के 2 बड़े फैसले

- बिहार में जमाबंदी निरस्त को लेकर सरकार अभियान चला रही है. इसी बीच पटना हाई कोर्ट ने अपने 2 फैसले में सरकार को बड़ा झटका दिया है
- हाई कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अधिकारी जज नहीं हैं. सरकार के अधिकारी मनमाने तरीके से जमाबंदी निरस्त नहीं कर सकते

सम्राट सरकार के लिए झटका क्यों है?

बिहार में जमाबंदी और जमीन विवाद को लेकर पटना हाई कोर्ट ने अपने 2 फैसले में सरकार को बड़ा झटका दिया है. दोनों ही फैसले में हाई कोर्ट ने यह साफ किया कि जमाबंदी को बिहार सरकार या उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कोर्ट के निर्देश के बिना रद्द नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट का यह दोनों फैसला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब बिहार सरकार अवैध जमीन के नाम पर जमाबंदी रद्द के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है।

जनवरी 2026 में एक सरकारी आदेश में कहा गया कि अवैध जमीन से संबंधित मामलों की तुरंत सुनवाई की जाए, जरूरत पड़ने पर जमाबंदी रद्द की जाए. अधिकारियों को इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 45 दिनों का वक्त दिया गया था।

जमाबंदी को लेकर हाई कोर्ट के 2 फैसले

1. 25 जून को जस्टिस सौरेंद्र पांडेय की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया. मामला जमुई के खैरा अंचल का था. करीब 60 साल पुराने इस मामले में अंचलाधिकारी भूमि मालिक की जमीन की रसीद नहीं काट रहे थे. उनका तर्क था कि इस जमीन की जमाबंदी पहले ही रद्द की जा चुकी है. सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जमाबंदी रद्द करने का अधिकार केवल सक्षम न्यायालय के पास है. अधिकारी अपने स्तर पर ऐसा फैसला नहीं कर सकते।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के अधिकारियों को फटकार भी लगाई, अदालत ने कहा कि अधिकारी जज बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो उचित नहीं है. यदि किसी की जमाबंदी (दाखिल-खारिज) गलत है, तो उसे अदालत में चुनौती दीजिए. अदालत जो भी फैसला दे, उसका कानून के अनुसार पालन कराइए।

2. 26 जून को पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा- बिना नोटिस दिए सरकार किसी भी जमीन की जमाबंदी को रद्द नहीं कर सकती है. मामला कटिहार का था, जिसमें याचिकाकर्ता का कहना था कि पिछले 39 साल से उनके पास जमीन का कब्जा था. अब सरकार ने अचानक से बिना नोटिस दिए जमाबंदी को रद्द कर दिया. कोई कारण नहीं बताया गया।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसे गलत करार दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि जमाबंदी रद्द का जो आदेश था, उसमें कोई खास कारण नहीं बताया गया है. सरकार ने पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया. ऐसे में कोर्ट ने मामले में जमाबंदी को बहाल फैसला दिया।

बिहार में जमीन विवाद के आंकड़े

बिहार सरकार के मुताबिक, म्यूटेशन से जुड़े 3 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. वहीं, फरवरी 2026 में सरकार ने विधानसभा को बताया कि ऑनलाइन समाधान पोर्टल पर 46 लाख मामले दर्ज हुए थे, जिनमें से केवल 6 लाख का ही निपटारा हो सका था। भूमि विवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बिहार सरकार ने रजिस्ट्री के नियमों में भी बदलाव किया है.

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार बिहार में हर तीसरी हत्या के पीछे जमीन विवाद होता है. मसलन, वर्ष 2025 में राज्य में हत्या के 224 मामले दर्ज हुए, जिनमें 67 हत्याएं जमीन विवाद से जुड़ी थीं. इसी तरह, 2024 में हत्या के 344 मामले दर्ज हुए थे, जिनमें 88 मामले जमीन विवाद से संबंधित थे।

दुष्कर्म पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए काफी: हाई कोर्ट

- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म 'कानूनी शब्द' है और पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है। कोर्ट ने 44 साल पुराने एक दुष्कर्म मामले में अभियुक्त राकेश की सात साल की सजा बरकरार रखी और 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि दुष्कर्म 'कानूनी शब्द' है ना कि 'मेडिकल'। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए काफी है। न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ दुष्कर्म के 44 साल पुराने मामले में अभियुक्त राकेश की आपराधिक अपील खारिज कर दी है और सात साल की सजा को बरकरार रखा है। अभियुक्त पर 50 हजार रुपये जुर्माना और लगा दिया है। कहा है कि यह राशि एक महीने के भीतर पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाए। अगर पीड़िता की मृत्यु हो चुकी है तो अपीलार्थी राशि उसके कानूनी वारिसों को देगा। जुर्माना न देने पर छह महीने की और कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। सत्र न्यायालय ने मई 1983 में सजा सुनाई थी। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। अपीलार्थी के वकील का कहना है कि उसके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। पीड़िता और अभियोजन के अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं। अभियुक्त को इसलिए प्रोबेशन पर रिहा करना चाहिए क्योंकि मामला लगभग 42 वर्षों से कोर्ट में लंबित है और उसकी उम्र 60 साल से अधिक है। यह प्रकरण प्रयागराज (पूर्ववर्ती इलाहाबाद) के कैंट थाने में दर्ज हुआ था। राजापुर निवासी नाबालिग पीड़िता ने अपनी गवाही में बताया था कि 22 फरवरी 1982 की सुबह करीब 9.30 बजे जब वह नाले के पास शौच के लिए गई थी तो मोहल्ले में ही रहने वाले अभियुक्त वहां मौजूद थे। सबसे पहले राकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर प्रकाश ने। विरोध करने पर उसे मारा-पीटा। पीठ ने गंगा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2013) मामले में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का उल्लेख भी किया कि दुष्कर्म पीड़िता के साक्ष्य को पुष्टि की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने अपीलार्थी के वकील की यह दलील भी भरोसेमंद नहीं मानी कि पीड़िता का चरित्र खराब था। कहा, प्रकरण में पीड़िता का बयान मेडिकल साक्ष्य से भी मेल खाता है, जिसमें शरीर पर छह चोटें दर्ज थीं। तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट ने रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को धारा 376 आइपीसी के तहत सही दोषी ठहराया है। हाई कोर्ट ने 23 जून को सुनाए गए अपने निर्णय में जमानत मुचलका तत्काल प्रभाव से रद करते हुए यह भी कहा है कि अगर अपीलार्थी जमानत पर है तो उसे बाकी बची सजा काटने के लिए 10 दिन के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट में समर्पण करना होगा। ऐसा नहीं होता तो ट्रायल कोर्ट तुरंत कानूनी कार्रवाई करे। अपीलार्थी को धारा 428 सीआरपीसी के तहत 'सेट-आफ' का लाभ मिलेगा। यानी मुकदमे के दौरान हिरासत में बिताई गई अवधि सजा में से घटाई जाएगी।

संक्षिप्त ख़बरें

दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़। थाना लीलापुर के उ0नि0 दीपक कुमार यादव व उ0नि0 विपिन चन्द्र यादव मय हमराह के द्वारा वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0न0 477/18, मु0अ0सं0 115/2018 धारा 147,148, 149, 323, 504, 506 आईपीसी व 3(1) × एससी एसटी एक्ट थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्तों विजय उर्फ दिग्विजय पुत्र रामअंजोर निवासी ग्राम हदिराही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष व राकेश कुमार वर्मा पुत्र हरीलाल वर्मा निवासी ग्राम हदिराही थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

बूथ संख्या 27 पर सुनी गई मन की बात

बिस्कोहर (सिद्धार्थनगर)। रविवार को बूथ संख्या 27, संग्रामपुर स्थित शक्ति केंद्र प्रथम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 135वें एपिसोड का भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक श्रवण किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के विचारों एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष राम नरेश पासवान, मंडल मंत्री हीरा मिश्रा, शक्ति केंद्र संयोजक डॉ. रामसूरत शर्मा, तोलन गुप्ता, अमरेश पासवान आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एसपी ने तीन पुलिस अधिकारियों के किये स्थानांतरण

प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर द्वारा सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारीगण को तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया गया है।जिनमें प्रशान्त राज क्षेत्राधिकारी नगर को क्षेत्राधिकारी रानीगंज, आशुतोष मिश्रा क्षेत्राधिकारी लालगंज को क्षेत्राधिकारी नगर, राजीव द्विवेदी पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़ को क्षेत्राधिकारी लालगंज, प्रतापगढ़ के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

बिजली सप्लाई में यूपी देश का नंबर-1 राज्य, महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़कर उत्तर प्रदेश ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरीन बिजली व्यवस्था लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। भीषण गर्मी, बढ़ती बिजली मांग और प्राकृतिक बाधाओं के बावजूद उप्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रहा है। इसे योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। वही मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और यूपीपीसीएल के कुशल प्रबंधन से यूपी देश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति करने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। विशेष बात यह है कि उत्तर प्रदेश लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए बिजली आपूर्ति के नए मानक स्थापित कर रहा है। 19 जून से उत्तर प्रदेश लगातार डिमांड बिजली आपूर्ति में देश का नंबर-1 राज्य बना हुआ है। उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े औद्योगिक राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से भी आगे निकलकर अपनी क्षमता साबित की है। इस तरह बिजली मांग के मामले में यूपी ने देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है।

24 जून को रिकॉर्ड 32,673 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई

अगर डिमांड बिजली आपूर्ति पर नजर डालें तो 27 जून को उत्तर प्रदेश में 31949 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई। इसी तरह 26 जून को 31,839 मेगावाट और 25 जून को 31,852 मेगावाट की आपूर्ति दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, 24 जून को उत्तर प्रदेश ने नया इतिहास रचते हुए रात करीब 9:51 बजे 32,673 मेगावाट की रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति की थी। यह अब तक की सर्वाधिक पीक डिमांड आपूर्ति थी। इसके पहले 23 जून की रात 10:26 बजे 32,405 मेगावाट बिजली आपूर्ति की गई थी। इसी तरह 22 जून को 31,841 मेगावाट, 21 जून को 32,348 मेगावाट, 20 जून को 31,549 मेगावाट और 19 जून को 30,968 मेगावाट बिजली आपूर्ति दर्ज की गई।

महानगर से लेकर गांव तक मिल रही लगातार बिजली

योगी सरकार में प्रदेश के शहरों से लेकर गांव तक निर्बाध बिजली आपूर्ति की जा रही है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी जैसे महानगरों में लगातार 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी 22 से 24 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। इस तरह जो प्रदेश 2017 से पहले बिजली कटौती और खराब आपूर्ति व्यवस्था के लिए चर्चा में रहता था, वही आज रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति और मजबूत ऊर्जा प्रबंधन के लिए देशभर में मिसाल बन गया है।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने बताया कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में लगे हुए कार्मिक दिन-रात परिश्रम कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा ही है। यूपीपीसीएल उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए कृत संकल्पित है। निदेशक वितरण ज्ञानेंद्र धर द्विवेदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने जिस तरह रिकॉर्ड स्तर पर डिमांड बिजली आपूर्ति की है, वह हमारी मजबूत विद्युत अवसंरचना, बेहतर प्रबंधन और टीमवर्क का परिणाम है।

खेत पर कब्जे का विरोध करना महिला को पड़ा भारी, दबंगों ने लाठी-डंडों से पीटा

दलित महिला ने चार लोगों पर लगाया जबरन बुआई और मारपीट का आरोप, कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

ललितपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कल्यानपुरा में खेत पर कथित कब्जे का विरोध करना एक दलित महिला को महंगा पड़ गया। महिला का आरोप है कि गांव के चार लोगों ने उसके खेत में जबरन बुआई शुरू कर दी और विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों व लात-घूंसों से मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम कल्यानपुरा निवासी रामवती पत्नी जगदीश अहिरवार ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 26 जून 2026 को सुबह करीब 10 बजे गांव के नन्नू, ध्यानी, लाडो तथा ध्यानी की पत्नी उसके खेत में जबरन बुआई कर रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो सभी आरोपी भड़क गए और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों और लात-घूंसों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण जगदीश, राहुल और पम्पू कुम्हार ने बीच-बचाव कर उसे आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया।

एक तरफ चलती रही LDA की कार्यशाला, दूसरी तरफ सील होते रहे कोचिंग संस्थान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। एक ओर एलडीए द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन जारी रहा, वहीं दूसरी ओर शहर में कोचिंग संस्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई भी लगातार चलती रही। इस कार्रवाई से छात्रों, अभिभावकों और कोचिंग संचालकों के बीच असमंजस, चिंता और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। संचालकों का कहना है की ज्यादातर कोचिंग किराए की प्रॉपर्टी में चल रही हैं और जो एलडीए के मानक हैं उन्हें मकान मालिक पूरी करने की जगह कोचिंग वाली जगह खाली करने को बोलने लगे हैं ऐसे में जाएँ तो जाएँ कहाँ। कम्पार्टमेंट परीक्षाओं में अब मात्र 15 दिन शेष हैं। ऐसे में अनेक विद्यार्थियों का कहना है कि विशेषकर कमजोर छात्र ऑनलाइन माध्यम से गणित, विज्ञान और अन्य जटिल विषयों को प्रभावी ढंग से समझ नहीं पाते। उनका मानना है कि इस समय ऑफलाइन कक्षाओं का बाधित होना उनकी तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कोचिंग संघ का कहना है कि लगातार

हो रही कार्रवाई के कारण कई शिक्षक और संस्थान ख़त्म होने की कगार पर हैं उनका दावा है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और कोचिंग संस्थान का करियर पूरी तरह चौपट हो जाएगा। प्रशासन का पक्ष है कि शहर में संचालित संस्थानों को निर्धारित नियमों और भवन सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक है, और कार्रवाई उन्हीं मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है परंतु उत्तर प्रदेश कोचिंग संघ के अध्यक्ष बादल चोपड़ा का कहना है ऐसे संस्थान जो अत्यंत छोटे हैं और उनके पास आवश्यक उपकरण हैं उन्हें बिना निरीक्षण , नोटिस दिए सील कर देना नियम विरुद्ध है इससे सम्पूर्ण समाज प्रभावित होता है।

सामुदायिक शौचालय पर लटक रहा ताला, ग्रामीण परेशान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रतनपुर/महराजगंज। नौतनवां ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेखुआनी चौराहे पर लाखों रुपये की लागत से बना सामुदायिक शौचालय विभागीय उदासीनता के कारण सफेद हाथी साबित हो रहा है। देखरेख के अभाव में विगत कई दिनों से इस शौचालय पर ताला लटक रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों को शौच के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। शासन की इस अनदेखी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है।हैरानी की बात यह है कि सरकार द्वारा इस शौचालय के नियमित रख-रखाव और साफ-सफाई के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को प्रति माह नौ हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

इसके बावजूद जिम्मेदार बजट की बंदरबांट में जुटे हैं। वर्तमान में स्थिति इतनी बदतर है कि नियमित सफाई न होने के कारण भवन से तीखी दुर्गंध उठ रही है। उचित रख-रखाव न होने से दीवारों की रंगाई-पुताई पूरी तरह बदरंग हो चुकी है, तथा घटिया निर्माण के कारण दीवारों पर लगे प्लास्टर और टाइल्स उखड़कर जगह-जगह से गिर रहे हैं।इस संबंध में एडीओ पंचायत रामकृष्ण प्रसाद ने कहा कि सामुदायिक शौचालय का बंद मिलना और गंदगी मिलना एक गंभीर लापरवाही है। इस मामले की तत्काल जांच कराकर संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

बलरामपुर के देवीपाटन मार्ग के चौड़ीकरण में भू-स्वामियों को हाई कोर्ट से राहत, आदेश-परेशान न करें

- हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई नियमानुसार

तुलसीपुर क्षेत्र में होना है मार्ग का चौड़ीकरण, विवाद में भूमि अधिग्रहण

बलरामपुर। देवीपाटन-तुलसीपुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने भू-स्वामियों को राहत देते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भू-स्वामी अपनी भूमि स्वेच्छा से बेचने को तैयार नहीं है तो उसे किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं लाया जा सकता। ऐसी स्थिति में सरकार को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत विधिक प्रक्रिया अपनानी होगी।

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया एवं न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश रिट याचिका संख्या 6489/2026, अनिल कुमार गुप्ता एवं आठ अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य की सुनवाई के दौरान पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में कहा था कि तुलसीपुर के ग्राम पाटन स्थित गाटा संख्या 271, 272 एवं 305 की भूमि सड़क चौड़ीकरण के लिए बिना वैधानिक अधिग्रहण प्रक्रिया अपनाए और उचित मुआवजा दिए जमीन लेने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि परियोजना के लिए लगभग 80 प्रतिशत भूमि बिक्री विलेख के माध्यम से खरीदी जा चुकी है तथा करीब 100 रजिस्ट्रियां भी हो चुकी हैं। सरकार ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं से सहमति बनाने के प्रयास सफल नहीं हो सके। याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि वे प्रस्तावित मूल्य पर भूमि बेचने को तैयार नहीं हैं तथा उन पर सहमति के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

कोर्ट ने कहा कि यदि दोनों पक्ष आपसी सहमति से मूल्य तय कर लें तो बिक्री विलेख कराया जा सकता है, लेकिन सहमति न बनने पर सरकार को कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए और उनकी सहमति जबरन प्राप्त करने का प्रयास न हो। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जो भू-स्वामी स्वेच्छा से भूमि बेचना चाहते हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। निर्देशों के साथ हाईकोर्ट ने याचिका का निस्तारण कर दिया।एसडीएम राकेश कुमार जयंत ने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ मामलों में नियमों से हटकर राहत देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जिस मकान की जितनी पुरानी आयु होगी, उसी के आधार पर उसका मूल्यांकन कर मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया विधिक प्रावधानों के अनुरूप और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराई जाएगी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ने रोशन की सुशील की एलईडी बल्ब यूनिट, बनाया आत्मनिर्भर

उत्तर प्रदेश में युवाओं की ऊर्जा और मेधा को सही दिशा देने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। आज का युवा केवल नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय खुद का उद्यम स्थापित करने की सोच रख रहा है। इस सोच को हकीकत में बदलने का काम प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं कर रही हैं। किसी भी राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब वहां के युवाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त अवसर और संसाधन मिलें। इसी उद्देश्य के साथ शुरू की गई योजनाएं राज्य के कोने-कोने में बदलाव की एक नई इबारत लिख रही हैं। सपने तभी साकार होते हैं जब उन्हें पूरा करने का अटूट साहस और सही समय पर उचित अवसर दोनों एक साथ मिल जाएं। प्रदेश सरकार की ''मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान'' योजना ठीक इसी तरह युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का माध्यम बन रही है। यह योजना युवाओं को रोजगार खोजने वाले पारंपरिक ढर्रे से बाहर निकालकर रोजगार सृजित करने वाला एक मजबूत और आत्मनिर्भर उद्यमी बनाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वित्तीय सहायता, सही मार्गदर्शन और प्रशासनिक सहयोग के अनूठे त्रिकोण के माध्यम से यह योजना आज प्रदेश के हजारों-लाखों युवाओं के जीवन में बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। इस योजना का प्रभाव केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और शहरी अंचलों के धरातल पर साफ देखा जा सकता है। जनपद लखीमपुर खीरी के एक छोटे से गांव के रहने वाले युवा श्री सुशील कुमार इस व्यवस्थागत बदलाव और व्यक्तिगत दृढ़ संकल्प की एक बेहद प्रेरणादायक मिसाल बनकर उभरे हैं।

तहसील मोहम्मदी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सदियापुर बलमियां बढ़कर के निवासी श्री सुशील कुमार के मन में हमेशा से अपना खुद का एक व्यवसाय स्थापित करने की तीव्र इच्छा थी। उनका यह स्पष्ट मानना था कि यदि स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के नए अवसर विकसित किए जाएं, तो इससे न केवल उनके खुद के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि क्षेत्र के अन्य ग्रामीण युवाओं को भी अपने घर के पास ही काम मिल सकेगा। उनके मन में काफी समय से एलईडी बल्ब निर्माण और उसकी असेंबली इकाई स्थापित करने का एक बेहतरीन विचार चल रहा था।

वर्तमान समय में देखा जाए तो ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण के अनुकूल एलईडी उत्पादों की मांग बाजार में लगातार तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में व्यवसाय की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। हालांकि, किसी भी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए जो सबसे पहली और आवश्यक चीज होती है, वह है पर्याप्त पूंजी। सुशील कुमार के लिए इस पूंजी की व्यवस्था करना ही उनके जीवन की सबसे बड़ी और कठिन चुनौती बनकर सामने खड़ी थी। सीमित आर्थिक संसाधनों और पारिवारिक बंधनों के कारण एक समय ऐसा भी आया जब उनका यह बड़ा सपना साकार होता हुआ नहीं दिख रहा था। वह लगातार संसाधनों को जुटाने के प्रयास में लगे हुए थे लेकिन हर बार वित्तीय कमी आड़े आ जा रही थी।

इसी कशमकश के दौरान उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई। इस जानकारी ने निराश हो चुके उनके मन को एक नई उम्मीद दी और उनके जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा देने का कार्य किया। योजना की बारीकियों को समझने के बाद श्री सुशील कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत एलईडी बल्ब असेंबली एवं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित विभागों द्वारा उनके व्यावसायिक प्रस्ताव का बेहद बारीकी से परीक्षण किया गया।

परियोजना की व्यवहारिकता, बाजार में इसकी मांग और सुशील कुमार के उत्साह को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इसे सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग प्रदान करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से उन्हें ?5 लाख का ऋण बेहद आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया गया। किसी भी नए उद्यम के लिए समय पर वित्तीय सहायता का मिलना संजीवनी के समान होता है। ठीक इसी तरह समय पर मिली इस आर्थिक मदद से सुशील कुमार के व्यवसाय की नींव बेहद मजबूत हो गई। लोन की राशि प्राप्त होते ही उन्होंने पूरी लगन, ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने उद्यम की स्थापना का जमीनी कार्य तुरंत प्रारंभ कर दिया।

ऋण की राशि का सही उपयोग करते हुए श्री सुशील कुमार ने सबसे पहले व्यवसाय के लिए आवश्यक मशीनरी, अत्याधुनिक उपकरण एवं कच्चे माल की उचित व्यवस्था की। इसके बाद उन्होंने अपने गांव के पास ही एलईडी बल्ब असेंबली एवं निर्माण इकाई को पूरी तरह स्थापित कर दिया। उनकी मेहनत का ही परिणाम था कि बेहद कम समय के भीतर ही उनकी यूनिट में उत्पादन का कार्य सुचारू रूप से प्रारंभ हो गया। आज उनकी इस निर्माण इकाई में विभिन्न प्रकार के उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्बों का निर्माण और उनकी असेंबली का कार्य सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। अपनी गुणवत्तापूर्ण निर्माण नीति और ग्राहकों के बीच बनाए गए अटूट विश्वास के बल पर उनका यह छोटा सा व्यवसाय अब निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

स्थानीय बाजार में बढ़ती हुई मांग के अनुरूप वे अपने उत्पादन की क्षमता में भी लगातार वृद्धि कर रहे हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत पहलू यही है कि यह योजना केवल किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापक स्तर पर स्थानीय रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। श्री सुशील कुमार की यह एलईडी यूनिट आज इसी उद्देश्य का एक उत्कृष्ट और जीवंत उदाहरण बनकर सबके सामने खड़ी है। आज उनके इस छोटे से कारखाने में स्थानीय स्तर के ही 5 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।

इन युवाओं को अब काम की तलाश में अपने घर और गांव को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ पलायन नहीं करना पड़ता। इससे न केवल उन श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्वरोजगार और उद्यमिता के प्रति एक बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान वातावरण का विकास हुआ है। जो सुशील कुमार एक समय स्वयं अपने लिए रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, आज वे अपनी मेहनत के दम पर अन्य लोगों को सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। व्यवसाय की इस शानदार सफलता ने श्री सुशील कुमार की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

आय बढ़ने से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हुई है और उनके रहन-सहन के स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आया है। इस आर्थिक आत्मनिर्भरता ने न केवल उनके परिवार को संबल दिया है, बल्कि सुशील कुमार के भीतर एक नए आत्मविश्वास का संचार भी किया है। सुशील कुमार आज बताते हैं कि यदि उन्हें प्रदेश सरकार की इस योजना का समय पर सहयोग न मिला होता, तो उनके जैसे एक सामान्य ग्रामीण युवा के लिए अपने दम पर इस तरह के व्यवसाय की स्थापना करना अत्यंत कठिन और असंभव सा होता।

योजना के माध्यम से प्राप्त वित्तीय सहायता और जिला प्रशासन के प्रशासनिक सहयोग ने सुशील कुमार के पुराने सपनों को धरातल पर सच करने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया। आज वे समाज में एक सफल और प्रतिष्ठित उद्यमी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना चुके हैं। श्री सुशील कुमार की यह शानदार सफलता की कहानी प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए एक महान प्रेरणास्रोत बन चुकी है। यह कहानी समाज को यह स्पष्ट संदेश देती है कि यदि हमारे युवा सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करें और शासन द्वारा संचालित लोककल्याणकारी योजनाओं का सही समय पर लाभ उठाएं, तो सीमित आर्थिक संसाधन भी कभी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकते।

दृढ़ संकल्प, अनवरत परिश्रम और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का यह अनूठा समन्वय किसी भी प्रतिभावान युवा को आत्मनिर्भरता के शिखर पर पहुंचा सकता है। आज सुशील कुमार सिर्फ अपने व्यवसाय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अपने आसपास के क्षेत्र के अन्य बेरोजगार युवाओं को भी स्वरोजगार अपनाने और प्रदेश सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। उनकी यह जमीनी सफलता अन्य ग्रामीण युवाओं के भीतर भी यह दृढ़ विश्वास पैदा करती है कि सरकार की तरफ से मिले सहयोग का सही उपयोग करके अपनी योजनाओं को साकार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस दूरदर्शी सोच और युवाओं की लगन का ही परिणाम है कि आज प्रदेश का औद्योगिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और ग्रामीण स्तर पर आत्मनिर्भरता के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी

महाराष्ट्र में TET का पेपर लीक: 'भरोसा' कब लीक होना बंद होगा?

संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

देश में पेपर लीक की समस्या एक बड़ा रुप ले चुकी है और इस पर राजनीति भी बहुत हो रही है। लेकिन लेकिन अभी तक लीक प्रूफ परीक्षा का हमें ऐहसास नहीं हो पा रहा है। नीट का पेपर जब लीक हुआ तो उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद महाराष्ट्र में टैट का पेपर लीक हो गया और राज्य सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 28 जून 2026 को होने वाली महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHA TET से ठीक 24 घंटे पहले पेपर लीक हो गया। नतीजा: 4 लाख 28 हजार अभ्यर्थियों का भविष्य फिर से लटका दिया गया। ये कोई पहली बार नहीं है। सवाल वही है: आखिर पेपर लीक से छुटकारा कब मिलेगा? 27 जून की सुबह का 'ऑपरेशन लीक' भिवंडी में छापा- 27 जून को सुबह 4 बजे भिवंडी पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि TET का पेपर बेचा जा रहा है। छापेमारी में संदिग्धों के पास से जो प्रश्नपत्र मिले, वो असली TET पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे। परीक्षा रद्द- महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद MSCE ने तुरंत 28 जून की परीक्षा स्थगित कर दी। नई तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।

गिरफ्तारियां- भिवंडी पुलिस ने कम से कम 3 लोगों को हिरासत में लिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू की है। ये पहली बार नहीं: 'बार-बार लीक' की कहानी- महाराष्ट्र में TET पेपर लीक अब आदत बन चुका है। 2025 कोल्हापुर में 23 नवंबर की परीक्षा से पहले 18 लोग गिरफ्तार। गिरोह 3 लाख रुपये में पेपर बेच रहा था। 2026 ठाणे/भिवंडी में 28 जून की परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक। 4 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। 2025 में कोल्हापुर केस के बाद भी परिषद ने कहा था कि 'पेपर छपाई बेहद गोपनीय होती है, कोषागार में 24 घंटे निगरानी रहती है '। फिर भी लीक हो गया। कौन फंस रहा है बीच में? 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी। इस बार करीब 4.28 लाख उम्मीदवार परीक्षा देने वाले थे। इसमें 2.26 लाख वो शिक्षक भी शामिल थे जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन TET क्वालिफिकेशन के लिए फिर से परीक्षा दे रहे थे। एक अभ्यर्थी का 1 साल बर्बाद। फीस, तैयारी, कोचिंग सब गया। और सबसे बड़ा नुकसान: स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती फिर लटकेगी।

लीक होता कैसे है? 'माफिया का मॉडल'- जांच और पुराने केस देखें तो पैटर्न साफ है। व्हाट्सएप चेन- HSC बोर्ड पेपर लीक में भी 'टेक वन' ग्रुप से 'एक्सीलेंट ट्यूशन क्लासेस' होते हुए स्टूडेंट्स तक पेपर पहुंचता था। प्राइवेट कोचिंग का रोल- नागपुर बोर्ड केस में एक प्राइवेट कोचिंग से जुड़े व्यक्ति ने पैसे लेकर पेपर साझा किया था। अंदरूनी सांठगांठ- बिना छपाई वाले, या कोषागार/ट्रांसपोर्ट लेवल पर पेपर निकलना। 2026 में भी पेपर परीक्षा से 20 मिनट पहले व्हाट्सएप पर भेजा गया था।

राजनीति शुरू: 'पेपर लीक सरकार' का आरोप- कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा: 'पेपर लीक अब अपवाद नहीं, बीजेपी सरकार की पहचान बन गया है। ठाणे में ही टैट का पेपर लीक... किसका राजनीतिक संरक्षण है?' आखिर लीक से छुटकारा कब? कड़ी सजा का कानून- NEET की तरह महाराष्ट्र में भी 'Public E&amination Act' को दांत वाला बनाना। गिरफ्तार लोग 2 महीने में जमानत पर बाहर न आएं। टेक्नोलॉजी से निगरानी- पेपर को ब्लॉकचेन या एन्क्रिप्टेड क्क्रकोड से ट्रैक करना। हर हैंडलिंग पर बायोमेट्रिक लॉग। कोचिंग माफिया पर कार्रवाई- ट्यूशन क्लासेस में छापे और व्हाट्सएप ग्रुप मॉनिटरिंग। पैसे लेकर पेपर बेचने वालों का लाइसेंस रद्द। परिषद की जवाबदेही- हर लीक पर MSCE के शीर्ष अधिकारी से स्पष्टीकरण और जिम्मेदारी तय। सिर्फ 'पुलिस का मामला' कहकर पल्ला झाड़ना बंद। अभ्यर्थियों को मुआवजा-परीक्षा रद्द होने पर फीस वापस + अगली परीक्षा फ्री + ट्रैवल खर्च। ताकि सिस्टम को दर्द हो। NEET, HSC, अब TET... हर बार सरकार कहती है 'जांच होगी '। पर अभ्यर्थी हर बार नई तारीख का इंतजार करता है। जब तक पेपर लीक करने वाले को नौकरी नहीं, बल्कि जेल और 10 साल का बैन मिलना तय नहीं होगा, तब तक 4 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगता रहेगा। क्या महाराष्ट्र को हर परीक्षा के लिए CBI जांच चाहिए, या MSCE खुद को सुधारेगा? अब हर परीक्षा से पहले लीक का डर परीक्षार्थियों को सताने लगा है। और जब वह किसी परीक्षा की तैयारियां करते हैं तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि कहीं परीक्षा लीक न हो जाए। सरकार को इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कानून को और सख्त बनाना होगा।

गांव का पुस्तकालय- विकसित भारत की पहली प्रयोगशाला

[ज्ञान का दीप गांव में जले, तभी विकास का सूरज पूरे देश में उगेगा]

[विकास वहीं जन्म लेता है, जहां प्रतिभा को अपना गांव छोड़ना नहीं पड़ता]

विकास की सच्ची पहचान चौड़ी सड़कों या बड़े उद्योगों से नहीं, बल्कि अवसरों की समान पहुंच से होती है। जब प्रतिभा को अपने ही गांव में भविष्य गढ़ने का अवसर मिले, तभी लोकतंत्र सार्थक होता है। हरियाणा ने 'अटल ई-पुस्तकालय' अभियान से यह उदाहरण प्रस्तुत किया है। राज्य के 985 से अधिक गांवों में स्थापित आधुनिक पुस्तकालय केवल अध्ययन-कक्ष नहीं, बल्कि लाखों ग्रामीण युवाओं के सपनों के नए आधार बन चुके हैं। यहां नवीनतम पुस्तकें, डिजिटल अध्ययन-सुविधाएं, तीव्रगति इंटरनेट, शांत वातानुकूलित वातावरण और एकाग्र अध्ययन का अनुकूल परिवेश उपलब्ध है। परिणामस्वरूप गांव का युवा अब अपने ही गांव से प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस सेवा, बैंक, कर्मचारी चयन आयोग, शिक्षक भर्ती तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरे आत्मविश्वास के साथ कर रहा है।

इस पहल की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल पुस्तकालयों का निर्माण नहीं, बल्कि उस धारणा को बदलना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल शहरों की पहचान है। वर्षों तक बेहतर संसाधनों की तलाश में ग्रामीण विद्यार्थियों को घर छोड़ना पड़ता था और शिक्षा परिवार पर आर्थिक बोझ बन जाती थी। हरियाणा ने यह स्थिति बदल दी है। अब गांव का विद्यार्थी अपने ही गांव में डिजिटल संसाधनों, राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन अभ्यास परीक्षाओं और नवीनतम अध्ययन सामग्री का लाभ उठाकर बिना पलायन अपने भविष्य की मजबूत नींव रख रहा है। यह केवल सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि शिक्षा के भूगोल में ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसने सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा का भविष्य स्थान नहीं, अवसर तय करते हैं।

इन पुस्तकालयों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने अध्ययन को व्यक्तिगत संघर्ष से सामूहिक शक्ति में बदल दिया है। गांव के युवा यहां साथ बैठकर तैयारी करते हैं, समसामयिक विषयों पर विचार-विमर्श करते हैं, एक-दूसरे की शंकाओं का समाधान करते हैं और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाते हैं। डिजिटल पुस्तकालय और तीव्रगति इंटरनेट उन्हें विश्वस्तरीय ज्ञान, नवीनतम अध्ययन सामग्री तथा बदलते परीक्षा-पैटर्न से निरंतर जोड़ते हैं। जिन सुविधाओं के लिए कभी बड़े शहरों की महंगी कोचिंग और किराए के कमरों पर निर्भर होना पड़ता था, वे आज गांव में ही उपलब्ध हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत हो रही है, साथ ही परिवार और समाज से जुड़ाव भी बना हुआ है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का सबसे सशक्त और जीवंत स्वरूप आज हरियाणा के इन ग्रामीण पुस्तकालयों में दिखाई देता है।

इस व्यवस्था की सबसे बड़ी शक्ति उसकी जमीनी भागीदारी है। पुस्तकालयों का संचालन केवल सरकारी तंत्र नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों की सक्रिय सहभागिता से हो रहा है। इसलिए प्रत्येक पुस्तकालय स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुआ है। जहां कृषि संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं की मांग है, वहां उसी अनुरूप अध्ययन सामग्री है; जहां सरकारी नौकरियों की तैयारी प्रमुख है, वहां आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। यह ऊपर से थोपा गया मॉडल नहीं, बल्कि गांव की जरूरतों से निर्मित व्यवस्था है। इसलिए युवा इन पुस्तकालयों को केवल सरकारी भवन नहीं, बल्कि अपने भविष्य और गांव की सामूहिक पूंजी मानते हैं। यही स्वामित्व-बोध किसी भी जनकल्याणकारी योजना की स्थायी सफलता का आधार बनता है।

शिक्षा विशेषज्ञ इस पहल को उचित ही 'ज्ञान का लोकतंत्रीकरण' कहते हैं। जब ज्ञान पर आर्थिक संसाधनों का एकाधिकार टूटता है, तभी सामाजिक न्याय का वास्तविक मार्ग प्रशस्त होता है। आज किसान का बेटा और मजदूर की बेटी भी उसी स्तर की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए कभी महंगी कोचिंग और शहर में रहना अनिवार्य माना जाता था। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में ग्रामीण युवाओं की भागीदारी और प्रशासनिक सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। मेरिट का आधार आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि प्रतिभा बनेगी। शिक्षा की यह समानता सामाजिक विषमताओं को भी कम करेगी। विकास तभी स्थायी होता है, जब उसकी धारा नीचे से ऊपर बहे। हरियाणा ने इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारकर दिखाया है।

अब प्रश्न केवल हरियाणा की सफलता का नहीं, बल्कि देश की विकास-प्राथमिकताओं का है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में आज भी लाखों युवा बेहतर अध्ययन-संसाधनों के लिए शहरों की ओर पलायन करते हैं। यदि प्रत्येक पंचायत में आधुनिक ई-पुस्तकालय स्थापित किए जाएं, तो यह केवल शिक्षा नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक समरसता और रोजगार के नए अवसरों का भी आधार बन सकता है। केंद्र सरकार को डिजिटल इंडिया, कौशल विकास और ग्रामीण विकास की योजनाओं से इस मॉडल को जोड़कर राष्ट्रीय अभियान का स्वरूप देना चाहिए। जिस प्रकार डिजिटल भुगतान और ग्रामीण इंटरनेट ने भारत की कार्यसंस्कृति बदली है, उसी प्रकार ज्ञान तक समान पहुंच का यह अभियान शिक्षा के परिदृश्य को नई दिशा दे सकता है। अब हर पंचायत में आधुनिक पुस्तकालय का सपना कल्पना नहीं, बल्कि एक सिद्ध, व्यवहारिक और राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने योग्य मॉडल है।

हरियाणा की यह पुस्तकालय क्रांति एक गहरी सीख देती है—राष्ट्र केवल राजधानी की ऊंची इमारतों से नहीं, गांवों के अध्ययन-कक्षों से भी बनता है। किसी ग्रामीण पुस्तकालय में देर रात तक जलती रोशनी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे युवा की आंखों का आत्मविश्वास और अपने ही गांव में भविष्य गढ़ने का संकल्प—यही लोकतांत्रिक विकास का सबसे प्रेरक दृश्य है। यह पहल केवल सरकारी नौकरियों की तैयारी का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण स्वाभिमान, सामाजिक समानता और अवसरों के विकेंद्रीकरण का सशक्त प्रतीक है। हरियाणा ने सिद्ध कर दिया है कि जब शिक्षा गांव के द्वार तक पहुंचती है, तब केवल विद्यार्थियों का भविष्य नहीं, पूरे समाज की दिशा बदल जाती है। अब समय है कि अन्य राज्य भी इस पथ पर आगे बढ़ें। क्योंकि जिस दिन भारत के हर गांव में ज्ञान का दीप समान रूप से प्रज्वलित होगा, उसी दिन विकास का वास्तविक सूर्योदय होगा। सच तो यह है कि जब गांव जागते हैं, तभी राष्ट्र आगे बढ़ता है।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत '

वेलकम टु द जंगल के कलेक्शन में आया तगड़ा उछाल, तीसरे दिन हाफ सेंचुरी पार पहुंचा आंकड़ा

लखनऊ। अक्षय कुमार की मल्टीस्टाररर फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। पेड प्रीव्यू में ही इसने शानदार कमाई कर ली थी और अब वीकेंड पर भी कमाल दिखा रही है। अहमद खान के निर्देशन में बनी 'वेलकम टू द जंगल' पॉपुलर 'वेलकम' फ्रैंचाइजी की तीसरी फिल्म है।

फरीदा जलाल के स्पेशल अपियरेंस

फिल्म ने पहले दिन 15.25 करोड़ रुपये की ओपनिंग की जबकि दूसरे दिन इसके कलेक्शन में 31.1% की अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। फिल्म को दर्शकों से पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। कई दर्शक खास तौर पर अनुभवी एक्ट्रेस फरीदा जलाल की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग की तारीफ कर रहे हैं, जो इस कॉमेडी एंटरटेनर की खासियतों में से एक बनकर उभरी है।

कितना रहा तीसरे दिन का कलेक्शन?

दूसरे दिन फिल्म ने वीकेंड पर 20 करोड़ रुपये की ओपनिंग की। वहीं सैकनिल्क के मुताबिक तीसरे दिन की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। वेलकम टू द जंगल ने तीसरे दिन 20.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। अभी तक इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन 59.75 करोड़ रुपये हुआ है। इस हिसाब से इसके कलेक्शन में 40 प्रतिशत का उछाल देखने को मिला। वहीं अभी ये कलेक्शन और बढ़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक अपने पहले रविवार को वेलकम टू द जंगल 22 से 23 करोड़ रुपये का कलेक्शन आराम से कर लेगी। वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 59.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है।

फिल्म में कौन-कौन से कलाकार आए नजर

फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, जाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, बृजेंद्र काला जैसे कलाकार नजर आए।

दैनिक राशिफल

मेष: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी और नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा तथा आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा।

वृषभ: कारोबार और नौकरी में प्रगति के संकेत हैं। पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात हो सकती है, जिससे भविष्य में लाभ के अवसर बनेंगे।

मिथुन: रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा।

कर्क: परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप सफलता से पूरा करेंगे।

सिंह: आत्मविश्वास के बल पर महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी भी निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें।

कन्या: व्यापार में लाभ के अच्छे योग हैं। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा तथा स्वास्थ्य का ध्यान रखने से दिन बेहतर रहेगा।

तुला: सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे और रुके हुए कार्यों में गति आएगी।

वृश्चिक: आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा।

धनु: करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मकर: कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का सहयोग भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

कुंभ: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।

मीन: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। धार्मिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी तथा मन शांत रहेगा।

रिमोट सेंसिंग तकनीक से फसलों का सटीक मानचित्रण से प्रदेश के किसानों का बढ़ा उत्पादन

लखनऊ कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश में फसलों की सही जानकारी, उनके क्षेत्रफल का आकलन और उत्पादन की प्रभावी योजना बनाना हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। परंपरागत सर्वेक्षण विधियों में समय, संसाधन और मानव श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इस चुनौती का समाधान प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन्स सेंटर (आरएसएसी) द्वारा उपग्रह आधारित तकनीकों का उपयोग कर प्रदेश की विभिन्न फसलों का वैज्ञानिक मानचित्रण एवं क्षेत्रफल आकलन किया जा रहा है।

रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तकनीकों की सहायता से प्रदेश के चयनित 20 जनपदों में केला फसल का ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर मानचित्रण तथा क्षेत्रफल आकलन किया गया है। इनमें गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कुशीनगर, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फतेहपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी, संत कबीर नगर, गोंडा, बस्ती और अम्बेडकर नगर जैसे प्रमुख जनपद शामिल हैं। इस पहल से केला उत्पादन वाले क्षेत्रों की सटीक पहचान संभव हुई है, जिससे किसानों और नीति निर्माताओं को बेहतर योजना बनाने में सहायता मिल रही है। अंतरिक्ष से किए गए मानचित्रण से किसानों को फसलोंत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। इसी प्रकार प्रदेश के 37 जनपदों में मेंथा फसल का भी ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर मानचित्रण और क्षेत्रफल आकलन किया गया है। बाराबंकी, सीतापुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, अलीगढ़, हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बिजनौर, अमरोहा, संभल, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, झांसी, जालौन, आजमगढ़, महाराजगंज, संत कबीर नगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बदायूं जैसे जनपद इस अध्ययन का हिस्सा रहे हैं। इससे प्रदेश में मेंथा उत्पादन के वास्तविक स्वरूप को समझने और उससे जुड़े उद्योगों के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराने में मदद मिली है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में जायद एवं रबी मौसम की सब्जी फसलों का ब्लॉक और जनपद स्तर पर मानचित्रण तथा क्षेत्रफल आकलन किया जा रहा है। यह कार्य प्रदेश की खाद्य सुरक्षा, बाजार प्रबंधन और कृषि योजनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सटीक आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकती है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत उपग्रह चित्रों का पूर्व-क्षेत्रीय विश्लेषण, फसलों की पहचान और वर्गीकरण, भू-सत्यापन, गुणवत्ता परीक्षण तथा क्षेत्रफल विश्लेषण जैसे वैज्ञानिक चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। वर्तमान में इन आंकड़ों के आधार पर विस्तृत मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं, जो कृषि प्रबंधन और निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित यह पहल दर्शाती है कि आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक केवल अनुसंधान तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों के खेतों तक पहुँचकर कृषि विकास की नई संभावनाएँ भी खोल रही है। रिमोट सेंसिंग और जीआईएस आधारित यह कार्य उत्तर प्रदेश को तकनीक-संचालित कृषि की दिशा में आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य में कृषि योजनाओं की सटीकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच कृषि को नई दिशा देती भू-स्थानिक तकनीक

उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। लेकिन बदलते जलवायु परिदृश्य, अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान, मिट्टी की उर्वरता में कमी तथा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव ने कृषि क्षेत्र के सामने नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। ऐसे समय में खेती को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और वैज्ञानिक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (आरएसएसी-यूपी) द्वारा 'जलवायु अनुकूलन कृषि एवं मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों का उपग्रहीय आंकड़ों से मानचित्रण' परियोजना संचालित की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर किसानों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सहायता प्रदान करना है। परियोजना के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) तथा वैश्विक स्थितिकरण प्रणाली (जीपीएस) जैसी आधुनिक भू-स्थानिक तकनीकों का उपयोग किया गया। इन तकनीकों के माध्यम से फसलों की स्थिति, मिट्टी की नमी, पोषक तत्वों की उपलब्धता तथा भूमि उपयोग में होने वाले परिवर्तनों का विस्तृत अध्ययन किया गया। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए मानचित्र तैयार किए गए, जिससे यह समझने में सहायता मिली कि कहाँ कृषि उत्पादन अधिक है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

आज कृषि क्षेत्र बढ़ती लागत और घटती उत्पादकता जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में भू-स्थानिक तकनीक किसानों को सटीक जानकारी उपलब्ध कराकर संसाधनों के बेहतर उपयोग में मदद करती है। इससे उर्वरकों, पानी और अन्य कृषि निवेशों का संतुलित उपयोग संभव होता है, जिससे लागत घटती है और उत्पादन बढ़ता है। साथ ही पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को भी कम किया जा सकता है। जलवायु अनुकूलन कृषि का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि कृषि प्रणाली को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना भी है। यह तकनीक किसानों को मौसम संबंधी जोखिमों को समझने, फसल चयन में सुधार करने तथा संसाधनों के संरक्षण में सहायता प्रदान करती है। इसके माध्यम से कृषि से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। परियोजना के अंतर्गत वाराणसी, एटा और देवरिया जनपदों के चयनित क्षेत्रों में अध्ययन कार्य किया गया। इन क्षेत्रों में भूमि उपयोग, जल स्त्रोतों, भू-जल, जलग्रहण क्षेत्रों तथा कृषि फसलों का विस्तृत मानचित्रण किया गया। कई वर्षों के आंकड़ों का विश्लेषण कर फसलों की स्थिति और स्वास्थ्य का मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही मिट्टी और जल के नमूनों का संग्रहण एवं परीक्षण कर उनकी गुणवत्ता का आकलन भी किया गया।

इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर किसानों को वैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। विशेष रूप से धान जैसी फसलों से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है तथा वैकल्पिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि और कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।

-अभिषेक सक्सेना, सहायक पर्यवेक्षक

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बन्धित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी का जीवन जनसेवा, न्याय और संस्कृति संरक्षण की अमर प्रेरणा- केशव प्रसाद मौर्य

● गाजियाबाद में उप मुख्यमंत्री ने किया लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी स्मृति द्वार का शिलान्यास

लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी ने भारतीय संस्कृति, धर्मस्थलों के संरक्षण और जनकल्याण के लिए किया अतुलनीय कार्य

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महापुरुषों और महान विभूतियों को मिल रहा है उचित सम्मान- केशव प्रसाद मौर्य

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज जनपद गाजियाबाद में 'लोकमाता' अहिल्याबाई होल्कर जी की 301वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह को बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लोनी बॉर्डर, बस डिपो के निकट विधायक निधि योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले 'लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी स्मृति द्वार' का शिलान्यास किया तथा 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी ने अपने आदर्श शासन, न्यायप्रिय व्यवस्था, लोककल्याणकारी कार्यों और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के माध्यम से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने अनेक धर्मस्थलों के संरक्षण एवं पुनर्निर्माण का कार्य किया तथा जनसेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी के महान योगदान को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद महान विभूतियों के योगदान को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। उनकी 300वीं जयंती का आयोजन पूरे देश और प्रदेश में श्रद्धा एवं गौरव के साथ किया गया। मौर्य ने कहा कि आज पूरा देश और प्रदेश लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी को नमन कर रहा है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से भारतीय संस्कृति, परंपराओं और महान व्यक्तित्वों को सम्मान देने का कार्य निरंतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी का जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्शों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और कल्याण पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए कहा कि विधायक नन्द किशोर गुर्जर निरंतर क्षेत्र के विकास और जनसेवा के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर सांसद अतुल गर्ग, विधायक नन्द किशोर गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष चौनपाल सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल, ब्लॉक प्रमुख कोमल गुर्जर, पार्षदगण, बीडीसी सदस्य, जनप्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

सम्पर्क सूत्र- बी0एल0 यादव

तालाब में 30 कुंतल मछलियां मरीं,मत्स्य पालक को लाखों का नुकसान

● तालाब में जहरीला पदार्थ डालने का आरोप,गांव के ही युवक पर जताया संदेह

न्याय के लिए चौकी से कोतवाली तक भटक रहा पीड़ित,कार्रवाई का इंतजार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज(रायबरेली)। सरेनी थाना क्षेत्र के तिवारीपुर कला गांव में तालाब में पाली गई मछलियों के संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिलने का मामला सामने आया है।घटना से मत्स्य पालक को लाखों रुपये के नुकसान का दावा किया गया है। पीड़ित ने गांव के ही एक युवक पर तालाब में जहरीला पदार्थ डालने का संदेह जताते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।तिवारीपुर कला निवासी हरिश्चंद्र पुत्र गोवर्धन के अनुसार,उन्होंने तालाब में मत्स्य पालन कर रखा था।उनका कहना है कि 27 जून की सुबह जब वह तालाब पर पहुंचे तो वहां लगभग सभी मछलियां मृत अवस्था में तैरती मिलीं।पीड़ित की मानें तो करीब 30 कुंतल मछलियां मर गई,जिससे उन्हें लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है।हरिश्चंद्र ने बताया कि तालाब में जहरीला पदार्थ डाल दिया,जिसके कारण मछलियों की मौत हुई।उन्होंने गांव के पिंटू निर्मल पर संदेह जताते हुए सरेनी थाने में तहरीर देकर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।पीड़ित का आरोप है कि भोजपुर पुलिस चौकी में शिकायत करने के बावजूद उसे अब तक न्याय नहीं मिला।वहीं रविवार को पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर भी मामले की शिकायत की है।पीडित का कहना है कि वह पुलिस चौकी भोजपुर और सरेनी कोतवाली के बीच लगातार चक्कर लगाने को मजबूर हैं,लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।वहीं,सूत्रों की मानें तो चौकी इंचार्ज भोजपुर द्वारा मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।अब क्या सच क्या झूठ यह पुलिस की जांच का विषय है।

संक्षिप्त खबरें

सड़क हादसे में मौत के मामले में अज्ञात ट्रक चालक पर मुकदमा दर्ज

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के सेमरपहा गांव के पास हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज किया है। हादसे में सरेनी थाना क्षेत्र के गाजीपुर गांव निवासी सर्वेश कुमार मौर्य की मौत हो गई थी। जबकि उनके भांजे आयुष मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतक के भाई राजेश मौर्य ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि सर्वेश और आयुष बुलेट बाइक से ऐहार में एक निमंत्रण समारोह से लौट रहे थे। सेमरपहा गांव के पास सड़क पर खड़े ट्रक से उनकी बाइक टकरा गई। हादसे में सर्वेश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आयुष गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर ट्रक के चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

पारिवारिक विवाद में युवक पर ईंट से हमला

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के बहाई गांव में शनिवार शाम पारिवारिक विवाद के दौरान मारपीट हो गई। आरोप है कि हमलावरों ने ईंट मारकर एक युवक को घायल कर दिया। उसके सिर और हाथ में गंभीर चोट आई। गांव निवासी मोहम्मद आरिफ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बिन्नी टोला निवासी गुलाम अहमद गांव में अपनी रिश्तेदारी में आए थे। इसी दौरान गांव के उनके चचेरे भाई निजामुद्दीन के साथ मिलकर पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट करने लगे। आरोप है कि दोनों ने ईंट से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की जमकर पिटाई

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में शनिवार शाम प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को युवती के परिजनों ने पकड़ लिया। इसके बाद गांव में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बनी रही। परिजनों ने युवक की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार, पूरे जबर सिंह मजरे मैदमऊ गांव निवासी अभिषेक युवती से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान युवती के परिजनों की नजर दोनों पर पड़ गई। परिजनों ने युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ कोतवाली ले गई। बताया जा रहा है कि युवक और युवती दूर के रिश्तेदार हैं। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि युवती के परिजनों की ओर से मामले में कोई तहरीर नहीं दी गई है। इसके चलते युवक का शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया है।

स्व0 1008 आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी द्वारा 41वां विशाल भंडारे का किया गया शुभारंभ

बिसवां, सीतापुर- हर वर्ष की तरह इस बार भी ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर बाबा खम्भेश्वर नाथ महादेव धाम में स्वर्गीय 1008 आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया 41 वां विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। महमूदाबाद रोड बिसवां स्थित खम्भेश्वर धाम में सोमवार, 29 जून को भव्य भंडारा लगेगा। मंदिर के पुजारी देन महाराज ने सभी भक्तों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे परिवार सहित भंडारे में पहुंचें, बाबा का आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य के भागी बनें। पुजारी देन महाराज ने बताया कि सोमवार को सुबह सबसे पहले बाबा खम्भेश्वर नाथ महादेव का विशेष पूजन और भोग लगाया जाएगा। इसके बाद भंडारे का शुभारंभ होगा। भंडारे में पूड़ी-सब्जी और बूंदी का प्रसाद वितरित किया जाएगा। देर शाम तक भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। खम्भेश्वर धाम में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भंडारे की परंपरा कई दशकों से चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन बाबा के दर्शन और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने से सारे कष्ट दूर होते हैं और मनोकामना पूरी होती है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, बहराईच, गोंडा और बाराबंकी से यहां पहुंचते हैं। नगर के भक्तों ने भंडारे की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाबा खम्भेश्वर नाथ महादेव धाम बिसवां-महमूदाबाद रोड पर स्थित है। पुजारी देन महाराज ने कहा बाबा का दरबार सबके लिए खुला है। जो भी सच्चे मन से आएगा, उसकी झोली जरूर भरेगी। सभी भक्त सोमवार को पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लें।

अक्षिता होम्स में फ्लैट और प्लॉट खरीदारों का हंगामा, डायरेक्टर पर धोखाधड़ी के आरोप

● पजेशन न मिलने से खरीदारों में नाराज़गी, तीन महीने में विकास कार्य और कब्जा देने की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित अक्षिता होम्स परियोजना को लेकर रविवार को फ्लैट और प्लॉट खरीदारों ने विरोध प्रदर्शन किया। खरीदारों ने अम्रपाली रिजॉर्ट के डायरेक्टर अजीत कुमार गुप्ता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि निर्धारित समय पर भुगतान करने के बावजूद उन्हें अब तक फ्लैट और प्लॉट का पजेशन नहीं मिला है। इसी मुद्दे को लेकर खरीदारों और अजीत कुमार गुप्ता के बीच तीखी बहस भी हुई। मौके पर मौजूद खरीदारों ने परियोजना में विकास कार्यों में देरी और बार-बार दिए गए आश्वासनों पर नाराज़गी जताई। उनका कहना था कि लंबे समय से केवल भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन जमीन पर अपेक्षित कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। विरोध कर रहे खरीदारों ने मांग की कि परियोजना में विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करते हुए अगले तीन माह के भीतर फ्लैट और प्लॉट का पजेशन सौंपा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समयसीमा में उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे संबंधित विभागों और पुलिस-प्रशासन से शिकायत करने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का सहारा लेंगे। वहीं, परियोजना प्रबंधन की ओर से खरीदारों की शिकायतों पर अपना पक्ष भी रखा गया। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बातचीत और बहस का दौर चलता रहा। फिलहाल खरीदार परियोजना के शीघ्र समाधान और समयबद्ध पजेशन की मांग पर अड़े हुए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन से संभव के तहत प्रत्येक नगर पंचायत में की जा रही जनसुनवाई

बाराबंकी। योगी सरकार के निर्देश तथा नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के मार्गदर्शन से संभव के तहत प्रत्येक नगर पंचायत में जनसुनवाई की जा रही है ईसी के तहत रामसनेहीं घाट के अधिशासी अभियंता संतोष चौधरी ने दिव्यांग दंपति की मदद की। पत्नी कमला देवी उम्र 62 वर्ष तथा पंछी लक्ष्मी नारायण उम्र 65 वर्ष जो कि बाराबंकी के नगर पंचायत रामसनेहीघाट चंदौली के निवासी हैं इनका वृद्धा पेंशन बनवाने में मदद की। और स्थानीय निवासियों के समस्या को देखते हुए निस्तारण करने का पूरा विश्वास दिलाया।

एस.एम.एस. लखनऊ में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'SPEEDS -2026' का शुभारंभ

● पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव अस्तित्व पर मंथन, जल एवं पर्यावरण संरक्षण पर विशेषज्ञों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज (एसएमएस), लखनऊ द्वारा डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू), लखनऊ तथा इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), लखनऊ लोकल सेंटर के सहयोग से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 'सोर्सेस ऑफ़ प्लेनेट एनर्जी , एन्विरोमेंटल और डिजास्टर साइंस (SPEEDS-2026)' का शुभारंभ आज एसएमएस परिसर में हुआ। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय 'पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण एवं मानव जीवन की स्थिरता' पर केंद्रित है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ. राजेन्द्र सिंह (वॉटरमैन ऑफ इंडिया), विशिष्ट अतिथि प्रो. (डॉ.) ओंकार सिंह, प्रोफेसर, एचबीटीयू, कानपुर तथा सुशील कुमार अग्रवाल, सीएमडी, गोबिंद इंडस्ट्रीज द्वारा पारंपरिक दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर प्रो. (डॉ.) आशीष भटनागर, निदेशक, एसएमएस लखनऊ, डॉ. भरत राज सिंह, महानिदेशक (तकनीकी) एवं सम्मेलन सह-अध्यक्ष तथा शरद सिंह, सीईओ एवं सचिव, एसएमएस लखनऊ भी मंचासीन रहे। स्वागत उद्बोधन देते हुए प्रो. (डॉ.) आशीष भटनागर ने कहा कि SPEEDS-2026 का विषय वर्तमान समय की वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। इश्.विजय प्रताप सिंह ,आ ईआई लखनऊ ने कहा कि यह सम्मेलन विद्यार्थियों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं एवं उद्योग जगत के विशेषज्ञों को पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श एवं ज्ञान-साझाकरण का सशक्त मंच प्रदान करेगा। मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ. राजेन्द्र सिंह ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में जल संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जनभागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं, बल्कि हमारी आध्यात्मिक धरोहर है। जब तक समाज प्रकृति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित नहीं करेगा, तब तक पर्यावरणीय समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं हो सकेगा। विशिष्ट अतिथि प्रो. (डॉ.) ओंकार सिंह ने कहा कि पर्यावरणीय संकटों का प्रभावी समाधान वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार एवं सतत विकास के समन्वित प्रयासों से ही संभव है। वहीं सुशील कुमार अग्रवाल ने उद्योग जगत की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरणीय उत्तरदायित्व एवं हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना समय की आवश्यकता है। डॉ. भरत राज सिंह, महानिदेशक (तकनीकी), एसएमएस लखनऊ एवं सम्मेलन सह-अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक पर्यावरणीय एवं आपदा संबंधी चुनौतियों के समाधान हेतु बहु-विषयक अनुसंधान और समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को मानव कल्याण, जल सुरक्षा एवं पर्यावरणीय संतुलन का आधार बताते हुए इसके संरक्षण पर विशेष बल दिया। अपने संबोधन में शरद सिंह, सीईओ एवं सचिव, एसएमएस लखनऊ ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों का दायित्व केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय जागरूकता विकसित करना तथा नवाचार आधारित व्यावहारिक समाधान उपलब्ध कराना भी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में होने वाले विचार-विमर्श सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

सम्मेलन के संयोजक डॉ. अरुणेश श्रीवास्तव ने बताया कि देशभर के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों से प्राप्त 110 से अधिक शोध-पत्रों में से तकनीकी समिति द्वारा गहन समीक्षा के उपरांत 81 शोध-पत्रों का सम्मेलन में प्रस्तुतीकरण हेतु चयन किया गया है। इन शोध-पत्रों में ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, जैव विविधता तथा सतत विकास से जुड़े समकालीन विषयों पर शोध प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम में डॉ. धर्मेन्द्र सिंह (एसोसिएट डायरेक्टर एवं सम्मेलन समन्वयक), डॉ. पी. के. सिंह (डीन एवं सम्मेलन सह-समन्वयक), सुरेन्द्र श्रीवास्तव (मुख्य महाप्रबंधक), रजिस्ट्रार, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण, शोधार्थी, उद्योग प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।

मलिहाबाद में 13 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर दी जान

● पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ/मलिहाबाद। मलिहाबाद थाना क्षेत्र के मोहम्मदनगर (रहमतनगर) गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 13 वर्षीय छात्रा ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही मलिहाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि घटना के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। मृतका की पहचान रानी (13 वर्ष) पुत्री मोहम्मद शोएब के रूप में हुई है। वह कक्षा 9 की छात्रा थी और नई बस्ती धनेवा स्थित विद्यालय में पढ़ाई करती थी। परिवार में पिता मोहम्मद शोएब, माता रीना, बड़ा भाई दाऊद (15 वर्ष) और छोटी बहन फरहीन (4 वर्ष) हैं। मलिहाबाद इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घटना के समय रानी के माता-पिता अपनी बुजुर्ग दादी के ऑपरेशन से संबंधित कार्य के लिए गांव में ही दूसरे घर गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और उसका बड़ा भाई दाऊद मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि रानी ने पहले अपने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजे में बेलन लगाकर उसे खोलने से रोक दिया। इसके बाद उसने घर के हॉल में लगे पंखे से दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। कुछ देर बाद जब माता-पिता घर लौटे तो घटना की जानकारी हुई। परिजन तत्काल रानी को फंदे से उतारकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलिहाबाद ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि भाई-बहन के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है, लेकिन आत्महत्या के वास्तविक कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लो वोल्टेज की समस्या से जन जीवन अस्त व्यस्त

बिसवां (सीतापुर)- बिजली के लो वोल्टेज से रामाभारी गांव के लोग महीनों से जूझ रहे हैं। इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते ग्रामीण वैसे ही त्राहि-त्राहि कर रहे हैं दूसरी ओर लगातार लो वोल्टेज के कारण बिजली उपभोक्ता बहुत परेशान हैं।बिजली का वोल्टेज इतना अधिक लो रहता है कि पंखों के केवल पर ही हिलते दिखते हैं लेकिन उनसे हवा नहीं मिलती। बल्वों से उजाला नहीं होता। गर्मी के प्रकोप से जूझ रहे लोग घरों के बाहर पेड़ों के नीचे शरण लेने को विवश हैं। सारे विद्युत उपकरण शो पीस बनकर रह गये हैं। खंभे पर लटकते जलते बल्व का प्रकाश ऐसा टिमटिमाते हुए दिखता है कि जैसे कोई जुगनू चमक रहा हो। इतने कम वोल्टेज में इन्वर्टर की बैटरी तक चार्ज नहीं हो पा रही हैं। अनेक बार शिकायत करने के बावजूद बिजली कर्मचारीयों व अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। भीषण गर्मी व बिजली वोल्टेज की कमी से बिल्लाये लोग प्रदेश की भाजपा सरकार को पानी पी-पीकर कोस रहे हैं। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार कमलेश मौर्य मृदु, वरिष्ठ भाजपा नेता खुशीराम मौर्य, पूर्व ग्राम प्रधान कबूल अहमद, पूर्व प्रधान निज़ाम अहमद, पूर्व बीडीसी सदस्य राजकुमार मौर्य तथा राकेश कुमार गौतम सहित दर्जनों उपभोक्ताओं ने रामा भारी गांव की लो वोल्टेज की समस्या का शीघ्र से शीघ्र समाधान कराये जाने की मांग की है। इस सम्बन्ध में प्रभारी अवर अभियंता बिसवां ग्रामीण रवी शर्मा ने बताया कि इन दिनों भीषण गर्मी होने व ट्रांसफार्मर की क्षमता से अधिक कनैक्शनों का लोड होने के कारण ऐसी समस्याएं आ रही हैं।यह पूरे क्षेत्र की समस्या है।ट्रांसफार्मरों की भार क्षमता बढ़ाये जाने तथा एक और ट्रांसफार्मर लगाये जाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही लो वोल्टेज की समस्या का समाधान हो जायेगा।

शराब ठेके के पास मिला मजदूर का शव, हड़कंप

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के गुरुबक्शगंज चौराहा स्थित शराब ठेके के पास रविवार सुबह एक मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चौराहे से उत्सव लॉन की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित हाते में एक युवक अचेत अवस्था में पड़ा मिला। सुबह दुकानदारों की नजर उस पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास देसी शराब और पानी के खाली पाउच भी पड़े मिले। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक शनिवार शाम से वहीं पड़ा था।

लोगों ने उसे शराब के नशे में समझकर ध्यान नहीं दिया। काफी प्रयास के बाद उसकी पहचान धनाभाद गांव निवासी बचान (30) पुत्र शीतलदीन के रूप में हुई। परिवारीजनों ने बताया कि बचान दैनिक मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी मौत से पत्नी मालती, दो बेटे और एक बेटी का रो-रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।

लखनऊ अग्निकांड : अंतिम चरण में SIT जांच, मंगलवार को शासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

● दमकल विभाग को मिली क्लीन चिट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ : अलीगंज सेक्टर-डी स्थित अवैध व्यावसायिक इमारत में हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। टीम ने सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद उनका क्रास चेक भी कर लिया है। शनिवार को जांच रिपोर्ट का प्रारूप तैयार कर लिया गया, जिसे मंगलवार को शासन को सौंपा जाएगा। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट के आधार पर कई विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि एसआइटी ने नगर निगम, अग्निशमन विभाग, एलडीए, बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभागों से प्राप्त रिपोर्टों का भी परीक्षण किया है। जांच के दौरान यह देखा गया कि भवन के निर्माण, संचालन और सुरक्षा मानकों के पालन में किस स्तर पर लापरवाही बरती गई। रिपोर्ट में विभागीय अधिकारियों की भूमिका और जवाबदेही भी तय की गई है। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट का इंतजार है। उसकी रिपोर्ट को शामिल किया जाएगा। उधर, अलीगंज पुलिस शनिवार को विभागों से रिपोर्ट मांग रही थी, ताकि रविवार को अपनी रिपोर्ट समिट कर सके। गौरतलब है कि बीते सोमवार को अलीगंज सेक्टर-डी में एक अवैध व्यावसायिक भवन में भीषण आग लग गई थी। आग इतनी तेजी से फैली कि भवन के भीतर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका। हादसे में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि कई नौ झुलसकर घायल हो गए थे। घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे को गंभीरता से लेते हुए तत्काल दो सदस्यीय एसआइटी का गठन किया था और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद एसआइटी ने लगातार घटनास्थल का निरीक्षण, दस्तावेजों की जांच और संबंधित लोगों से पूछताछ की। अब सभी की निगाहें एसआइटी रिपोर्ट पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद भवन स्वामी, प्रबंधन और लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई की दिशा तय होगी। शासन स्तर पर रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

यूपी में रोजगार और आजीविका को नई गति देगी वीबी-जी राम जी योजना -केशव प्रसाद मौर्य

● विकसित भारत-जी राम जी योजना का 2 जुलाई को होगा राज्यव्यापी जन सम्मेलन लॉन्च इवेंट कार्यक्रम- केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2026 से शुरू होगी वी.बी.जी. राम जी योजना

2 जुलाई को राज्यभर में जन सम्मेलन एवं 10,000 कार्यों का होगा शुभारंभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशो के क्रम मे ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के स्थान पर वी.बी.जी. राम जी (विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी पूरी कर ली है। योजना 1 जुलाई 2026 से पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशो के अनुपालन मे ग्राम्य विकास विभाग मुख्यालय द्वारा सभी जनपद, विकासखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा से संबंधित साइन बोर्ड, सूचना पट्टिकाओं आदि को अपडेट कर 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना, उत्तर प्रदेश' नाम अंकित करने के निर्देश दे दिये हैं। 2 जुलाई 2026 को राज्यव्यापी जन सम्मेलन लॉन्च इवेंट कार्यक्रम निर्धारित दिशा निर्देशो के अनुरूप होगा। 2 जुलाई 2026 को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर योजना का शुभारंभ होगा। इसके अनुरूप उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक विकास खण्ड की 02 ग्राम पंचायतों में जन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जन सम्मेलन में योजना के अंतर्गत कार्यों का शुभारंभ करना, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, श्रमिकों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं स्थानीय समुदाय के साथ जन सम्मेलन आयोजित होगा। प्रस्तावित कार्यों एवं विकसित ग्राम पंचायत योजना का प्रदर्शन किया जाएगा। विकसित भारत-जी राम जी योजना की मुख्य विशेषताओं, लाभों एवं 125 दिनों के रोजगार गारंटी पर प्रचार सामग्री (पोस्टर, बैनर, स्टैंडी) का प्रदर्शन करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश में कुल 10,000 कार्य 2 जुलाई को शुरू किए जाएंगे। सर्वाधिक कार्य शुरू करने वाले जनपदों में आजमगढ़ (342), जौनपुर (337), गाज़ीपुर (326), सीतापुर (319) आदि शामिल हैं। बता दें कि योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी को मजबूत करना है,आजीविका संवर्धन एवं विकसित ग्राम पंचायतों का निर्माण करना,पारदर्शिता, डिजिटल प्रणाली एवं विकेन्द्रीकृत योजना बनाना है। आयुक्त,ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देश दिये है कि जन सम्मेलन का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए तथा योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

सम्पर्क सूत्र- बी0एल0 यादव

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली के होटल में पुलिस की गुंडागर्दी, महिलाओं से मारपीट के आरोप में एसआई पर गिरी गाज

दिल्ली। आदर्श नगर इलाके में स्थित एक होटल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें थप्पड़ मारे गए। इस घटना की वीडियो प्रसारित होने के बाद सब इंस्पेक्टर हिमांशु को लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आदर्श नगर इलाके में स्थित होटल क्लाउड इन होटल, पंचवटी से पुलिस कार्रवाई का एक वीडियो प्रसारित हुआ। यह घटना तीन दिन पुरानी है और वीडियो में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस कार्रवाई के दौरान दो महिलाओं को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। देर रात होटल में दो पक्षों के बीच हुए विवाद की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान आरोपित पुलिसकर्मी ने एक महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में दो महिलाओं को थप्पड़ मारे। वहीं, मामले में दूसरा पक्ष भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दूसरे पक्ष की एक महिला भी झड़प में घायल हुई है। फिलहाल आदर्श नगर थाना पुलिस पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि फुटेज और दोनों पक्षों के आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में मौके पर मौजूद महिला पुलिस के भी बयान लिए गए हैं हालांकि उनके खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस फुटेज के आधार पर डीसीपी आकांक्षा यादव ने एसआई को लाइन हाजिर कर मामले की जांच जिले की सतर्कता शाखा को सौंप दी है। उनका कहना है कि बृहस्पतिवार देर रात करीब डेढ़ बजे महिलाओं के दो समूहों में झगड़े की सूचना मिली थी। इस जानकारी के बाद आदर्श नगर थाने से एसआई हिमांशु पुलिसकर्मियों के साथ होटल में पहुंचे। इनमें एक महिला के पैर से खून निकल रहा था। जांच में मालूम हुआ कि यह महिला तीन साथियों के साथ इस होटल में ठहरी थी। इसी होटल में बुराड़ी निवासी एक और महिला भी रुकी थी। बताया जाता है कि दोनों समूहों में रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया। घायल महिला का बीजेआरएम अस्पताल में मेडिकल कराया गया।अब पुलिस इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को जांच में शामिल करने के लिए नोटिस दिया है।

पुणे मंगेतर मर्डर केसः सिया-चेतन ने अपने 3 साल के प्लान के लिए ले ली केतन अग्रवाल की जान!

● सिया-चेतन की खौफनाक प्रेम कहानी ने लोगों के रौंगटे खड़े कर दिए हैं. दोनों पर मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या का आरोप है. केतन अग्रवाल की सिया से मंगनी हो चुकी थी. दोनों की शादी होने वाली थी, मगर इससे पहले ही उसकी मौत हो गई. अब दावा है कि 3 साल के प्लान के लिए चेतन और सिया ने केतन की हत्या कर दी.

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में खुलासों ने पूरे भारत को हैरान कर रखा है. मंगेतर की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर करने वाली सिया के कारनामे सभी को चौंका रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में यह बात सामने आई है कि सिया गोयल के प्रेमी चेतन चौधरी ने उससे शादी करने के लिए कम से कम तीन साल का समय मांगा था. फिलहाल सिया की उम्र 20 साल और चेतन की उम्र 22 साल है।

क्या था 3 साल वाला प्लान

साजिश के तहत, अगर केतन की हत्या हो जाती, तो परिवार में मातम के चलते अगले कुछ साल तक सिया की शादी की शायद बात नहीं उठती. इन तीन सालों में चेतन अपने करियर में सेटल होना चाहता था. वहीं, सिया को भी अगले तीन साल तक अपनी मर्जी से आजाद जिंदगी जीने का मौका मिल जाता. इसके बाद दोनों शादी करने वाले थे. इसी मंसूबे के चलते दोनों ने केतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया. आरोपियों की गूगल सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि उन्होंने हत्या किन-किन तरीकों से की जा सकती है, इससे जुड़े कई वीडियो देखे थे. जांच में यह भी साफ हुआ है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने इसी साल फरवरी महीने से ही केतन की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दिया था।

सिया की मां ने बेटी पर क्या कहा

सिया की मां पूजा गोयल ने घटना पर हैरानी जताते हुए कहा, 'जब मैंने इस घटना के बारे में सुना, तो हैरान रह गई. मैं सोचती रही कि ऐसा कैसे हो सकता है. केतन का परिवार आज जो दुख झेल रहा है, वह बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे और भी ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि दो परिवार बर्बाद हो गए हैं.'' उन्होंने कहा कि केतन बहुत अच्छा इंसान था. अगर इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, भले ही वह मेरी बेटी ही क्यों न हो.' उन्होंने कहा, 'अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती है, तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक दिया जाना चाहिए, जहां से केतन गिरा था।'

सिया के पापा ने बेटी पर क्या कहा

वहीं, सिया के पापा प्रवीण गोयल ने केतन की मौत पर दुख जताया और कहा कि केतन के परिवार के लिए यह नुकसान बहुत बड़ा है. प्रवीण गोयल ने कहा, 'जो हुआ वह बहुत दुखद घटना है. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है. उन्होंने अपना बेटा खो दिया है. मैं उससे बहुत प्यार करता था. मैं उससे इतना जुड़ा हुआ था कि मानो उसको अपना बेटा ही मानने लगा था. इतना प्यारा, होनहार और अच्छा लड़का आज हमने उसे खो दिया. एक पिता के तौर पर मैं कहूंगा, उन्होंने अपना बेटा खो दिया, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता. कुछ दिन पहले ही उन्होंने सिया का जन्मदिन मनाया था और आगे एक बेहतर जिंदगी के सपने देखे थे।'

सुनील शेट्टी ने बताई 15 महीने की नातिन इवाराह की सुबह की आदत, कहा- 'वह पीएम मोदी की तस्वीर को लड्डू खिलाती है'

● सुनील शेट्टी ने नातिन के बारे में कहा, वह मोदी जी मोदी जी कहती है और पीएम मोदी को लड्डू खिलाती है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली: वेलकम टू द जंगल एक्टर सुनील शेट्टी अक्सर अपनी नातिन इवाराह के बारे में बात करते हैं और उसकी आदतों का जिक्र इंटरव्यू में करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने टाइम्स नाओ के साथ बातचीत में खुलासा किया कि इवाराह की सुबह की दिनचर्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लड्डू चढ़ाना शामिल है. उन्होंने याद करते हुए कहा कि पीएम मोदी से इवाराह को एयरपोर्ट पर उनकी नैनी ने मिलवाया और तब से वह उनकी तरफ आकर्षित हुई. उन्होंने कहा, मैं हमेशा से उनका (पीएम मोदी) का फैन रहा हूं. मैं पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा. मैं एक लीडर के बारे में बता रहा हूं. अगर कोई लीडर मुझे खुश करता है तो करता है।

पीएम मोदी को खिलाती है इवाराह लड्डू

आगे उन्होंने कहा, मैं अपने देश से जितना प्यार करता हूं, उतना ही अपने मैन से भी करता हूं. उनमें कुछ तो खास बात है. मेरी नातिन 15 महीने की है. एक बार एयरपोर्ट पर उसकी नैनी ने उसे मोदी जी के बारे में बताया था. अब, वह हर सुबह साई बाबा की किताब खोलती है, जिसमें मोदी जी की भी तस्वीर है. वह फोटो खोलकर कहती है मोदी जी. वो गणपति जी की मूर्ति से लड्डू लेके आती है और उनको खिलाती है. मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा. ना ही उसके पेरेंट्स ने. यह उनके बारे में है. बहुत मैजिकल है। इवाराह के बारे में एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और क्रिकेटर केएल राहुल ने 24 मार्च 2025 में पहले बच्चे का स्वागत किया. वहीं बेटी का नाम केएल राहुल के बर्थडे पर इवाराह का खुलासा किया. इसका मतलब भगवान का तोहफा. हालांकि जन्म के बाद से ही लाइमलाइट से दूर रही हैं. वहीं खास मौकों पर उन्होंने बेटी की झलक तो दिखाई. लेकिन चेहरा नहीं. हालांकि सुनील शेट्टी ने बताया कि इवाराह अथिया 2.0 है।

विराग राजू थापर ने 'खत्री अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड', लुधियाना के चेयरमैन का संभाला पदभार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लुधियाना- कुछ रोज़ पहले पंजाब सरकार ने चिराग राजू थापर को खत्री अरोड़ा वेलफेयर बोर्ड, लुधियाना का चेयरमैन बनाया था और आज उनके सम्मान में एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें मुख्य रूप से जिला प्रधान जतिंदर खंगूड़ा, लोकसभा लुधियाना इंचार्ज शरण पाल मक्कड़, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर, पंजाब इंफोटेक के वाइस चेयरमैन प्रदीप खालसा, ब्राह्मण बोर्ड के चेयरमैन पंकज शारदा, पार्षद मनी राम भगत जी पहुंचे। जतिंदर खंगूड़ों ने कहा कि चिराग थापर लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्हें पहले भी अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और उसमें उनकी मेहनत को देखते हुए पार्टी ने उन्हें चेयरमैन के पद से सम्मानित किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में वह पार्टी को और मजबूत करेंगे।लोकसभा इंचार्ज शरणपाल मक्कड़ ने कहा कि चिराग थापर युवाओं के साथ मिलकर काम करेंगे और खत्री अरोड़ा समाज की भलाई के लिए भी बेहतर काम करेंगे।

चिराग थापर ने इस ज़िम्मेदारी के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप को धन्यवाद दिया और कहा कि वह इस ज़िम्मेदारी को पूरी लगन से निभाएंगे और पार्टी के लिए पूरी लगन से काम करेंगे। इस मौके पर पूर्व पार्षद बलजिंदर संधू, सुनील थापर, अमरजीत सिंह गोल्डी, राजेश महान, अनिल थापर, प्रभात शुक्ला, दीपक थापर, बंटी सहगल, अमित ग्रोवर, रॉबिन गोगना, विकास गोयल, गगनदीप ओबेरॉय, अशोक बिट्टू, हरदीप विक्की, राहुल शर्मा आदि मौजूद थे।

45 दिनों का काम चार वर्षों से अधूराः 1.34 करोड़ की डीप सीवर परियोजना बनी मधु विहार के हजारों लोगों के लिए खतरा

● 30 फीट गहरा खुला गड्ढा, घंटों का जाम और स्कूली बच्चों सहित हजारों लोगों की जान पर बना जोखिम; रणबीर सिंह सोलंकी ने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- द्वारका सेक्टर-3 स्थित मधु विहार में दिल्ली जल बोर्ड की डीप सीवर परियोजना लगभग चार वर्षों से अधूरी पड़ी होने के कारण स्थानीय निवासियों में गहरी चिंता और रोष व्याप्त है। परियोजना के तहत खोदा गया लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा आज भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं किया गया है। क्षेत्रवासियों के अनुसार इससे प्रतिदिन राहगीरों, स्कूली बच्चों महिलाओं वरिष्ठ नागरिकों तथा वाहन चालकों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है।जानकारी के अनुसार, मधु विहार में वर्षों से चली आ रही सीवर निकासी समस्या के स्थायी समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने डीप सीवर सिस्टम निर्माण का टेंडर स्वीकृत किया था। 27 अप्रैल 2022 को लगभग 1.34 करोड़ की लागत से कार्यादेश जारी किया गया। अनुबंध के अनुसार यह कार्य 45 दिनों में पूरा किया जाना था लेकिन निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के लगभग चार वर्ष बाद भी परियोजना अधूरी पड़ी है। परियोजना के तहत मधु विहार सी-ब्लॉक स्थित महाराणा प्रताप द्वार के निकट सर्विस रोड पर लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया।यह सर्विस रोड केवल एक सामान्य सड़क नहीं बल्कि मधु विहार के हजारों निवासियों की जीवनरेखा है। यही मार्ग मधु विहार को द्वारका सेक्टर-2 तथा आसपास के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों स्वास्थ्य सेवाओं, सामुदायिक सुविधाओं एवं मुख्य यातायात नेटवर्क से जोड़ता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में छात्र द्वारका सेक्टर-2 स्थित सरकारी विद्यालय एमसीडी प्राथमिक विद्यालय क्षेत्र में संचालित महिला सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र सामुदायिक भवन तथा भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज तक इसी मार्ग से पहुँचते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक एवं अन्य स्थानीय निवासी आरोग्य मंदिर डिस्पेंसरी पार्क तथा द्वारका गुरुग्राम पालम एवं आईजीआई पालम एयरपोर्ट सहित विभिन्न स्थानों तक आने-जाने के लिए भी इसी मार्ग का उपयोग करते हैं।स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले चार वर्षों के दौरान इस खुले गड्ढे के कारण कई दोपहिया वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल हुए हैं। 31 अक्टूबर 2023 को एक इको कार भी इस गड्ढे में गिर गई थी, जिसमें चालक गंभीर रूप से घायल हुआ था वर्तमान में मार्ग के एक हिस्से को बंद कर दिया गया है। सड़क निर्माण अधूरा होने के कारण इस मार्ग पर प्रतिदिन घंटों लंबा जाम लगा रहता है। दूसरी ओर की सर्विस लेन भी लगभग अनुपयोगी हो चुकी है, जिसके चलते अनेक दोपहिया वाहन चालकों को मजबूरी में गलत दिशा से वाहन चलाना पड़ता है। इससे दुर्घटना की आशंका और अधिक बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति प्रतिदिन हजारों लोगों के लिए परेशानी और जोखिम का कारण बनी हुई है फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम के चेयरमैन एवं समाजसेवी रणबीर सिंह सोलंकी ने कहा कि पिछले लगभग चार वर्षों से वे और क्षेत्रवासी लगातार दिल्ली जल बोर्ड तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतें एवं अनुरोध भेजते रहे हैं, लेकिन आज तक परियोजना पूरी नहीं हो सकी सोलंकी ने कहा यह केवल अधूरी निर्माण परियोजना का मामला नहीं है, बल्कि हजारों नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और जीवन से जुड़ा अत्यंत गंभीर विषय है। यह सर्विस रोड मधु विहार की जीवनरेखा है जहाँ से प्रतिदिन स्कूली बच्चे महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक नौकरीपेशा लोग और हजारों नागरिक आवागमन करते हैं। जिस परियोजना को मात्र 45 दिनों में पूरा होना था वह लगभग चार वर्ष बाद भी अधूरी है। नई सरकार को कार्यभार संभाले भी एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। जनता को उम्मीद थी कि वर्षों से लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। कुछ माह पूर्व जनकपुरी की दुखद घटना के बाद सुरक्षा के नाम पर केवल बैरिकेडिंग कर औपचारिकता पूरी कर दी गई जबकि स्थायी समाधान आज तक नहीं किया गया। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं बल्कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराना है ताकि किसी भी परिवार को टाली जा सकने वाली दुर्घटना का सामना न करना पड़े।सोलंकी ने माननीय उपराज्यपाल एवं माननीय मुख्यमंत्री, दिल्ली से मांग की है कि– डीप सीवर परियोजना को युद्धस्तर पर पूरा कराया जाए।लगभग 30 फीट गहरे खुले गड्ढे को तत्काल सुरक्षित कर आमजन के लिए मार्ग पूरी तरह बहाल किया जाए। परियोजना में हुई लगभग चार वर्षों की देरी की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों, संबंधित एजेंसी तथा ठेकेदार की जवाबदेही तय की जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी एवं प्रभावी वैकल्पिक यातायात व्यवस्था तत्काल लागू की जाए।उन्होंने कहा कि समय रहते आवश्यक कदम उठाकर किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सकता है। जनहित से जुड़े इस विषय में प्रशासन से शीघ्र संवेदनशील और ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली के फुटपाथों पर अतिक्रमण जारी, जोखिम में राहगीरों की जान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया था कि यह अधिकार मोटर वाहनों के विशेषाधिकार से ऊपर है। इसके बाद यह उम्मीद जगी थी कि संबंधित एजेंसियां अब इसके क्रियान्वयन में लग जाएंगी, लेकिन चार दिन बाद भी दिल्ली में कहीं भी फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए कोई बड़ा अभियान नहीं शुरू किया गया है। अब भी विभिन्न इलाकों में फुटपाथ पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग हो रही है, रेहड़ियां लगी हैं और दुकानदार अब भी अपनी दुकान का सामान फुटपाथ पर लगा रहे हैं। फुटपाथ पर अतिक्रमण का खामियाजा राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। उनको सड़क पर जाना पड़ता है, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। दिल्ली में हर साल 600 से अधिक राहगीरों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। वर्ष 2022 में फुटपाथ पर अतिक्रमण होने से सड़क पर चलने वाले 629 राहगीरों की सड़क हादसों में मौत हो गई थी। इसी तरह 2023 में 622, 2024 में 624 और 2025 में 649 राहगीरों की सड़क हादसों में मौत हो गई। इसके बावजूद एनडीएमसी, एमसीडी, पुलिस-प्रशासन अब तक कोई सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। निगमबोध घाट के सामने रिंग रोड के एक तरफ फुटपाथ पर दुकानदारों ने न केवल अपनी दुकानों का सामान फैला रखा है, बल्कि तिरपाल टांग कर रहने के लिए आशियाने भी बना लिए हैं। फुटपाथ पूरी तरह ब्लाक होने के कारण राहगीरों को मजबूरी में तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच मुख्य मार्ग या सर्विस लेन पर चलना पड़ रहा है। यही चिंताजनक स्थिति पुरानी दिल्ली और उसके आसपास के प्रमुख ऐतिहासिक बाजारों में भी है। चांदनी चौक स्थित टाउन हाल के समीप गांधी पार्क की दीवार के पास साइकिल और फुटपाथ पर मोटरसाइकिल खड़ी की जाती हैं। इससे राहगीरों को आवाजाही करने के लिए जगह नहीं बजती। इसी तरह श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के फुटपाथ को अब पूरी तरह से रिक्शा स्टैंड बना दिया गया है।

चित्तरंजन पार्क थाना पुलिस ने वाहन चोरी के दो मामलों का किया खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दक्षिण जिला पुलिस के चित्तरंजन पार्क थाना पुलिस ने वाहन चोरी के दो मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दो मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जो गोविंदपुरी थाना क्षेत्र से चोरी हुई थीं।पुलिस के अनुसार, 26 जून 2026 को हेड कांस्टेबल सज्जन और हेड कांस्टेबल सिरमोहर नियमित गश्त के दौरान अलकनंदा स्थित मंदाकिनी एन्क्लेव, गेट नंबर-6 के सामने पेट्रोल पंप के पास वाहन जांच कर रहे थे। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर उसकी जांच की गई।मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर का सत्यापन करने पर पता चला कि यह वाहन गोविंदपुरी थाना के ई-एमवीटी नंबर 002103/2026 में चोरी दर्ज था।पूछताछ के दौरान मोटरसाइकिल चला रहे सुमित कुमार सिंह ने बताया कि उसने यह बाइक सूरज सरकार से प्राप्त की थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सूरज सरकार को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से एक और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई, जो गोविंदपुरी थाना के ई-एफआईआर नंबर 032103/2023 में चोरी की दर्ज थी।पुलिस ने दोनों चोरी की मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया है। मामले में आगे की जांच जारी है। इस कार्रवाई को हेड कांस्टेबल सज्जन और हेड कांस्टेबल सिरमोहर की टीम ने थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अनीश शर्मा के नेतृत्व तथा एसीपी सी.आर. पार्क के समग्र पर्यवेक्षण में अंजाम दिया।गिरफ्तार

आरोपियों की पहचान 29 वर्षीय सूरज सरकार, निवासी टी.के.डी. गांव, नई दिल्ली तथा 18 वर्षीय सुमित कुमार सिंह, निवासी तुगलकाबाद, नई दिल्ली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है।

घाघरा ओर डीमोउ नदी की बाढ़ में 20 से अधिक गांव प्रभावित

● जलमग्न कृषिभूमि , पशुधनों को लेकर चिंतित किसान सरकार से मदद की गुहार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम धेमाजी। धेमाजी जिले की असम ओर अरुणाचल प्रदेश के सीमांत इलाके में हो रही तेज बारिश के वेज से अरुणाचल से धेमाजी जिला होकर बहती कई नदी उफान पर है। मुख्यरूप में सीमेन, डिमो, गगरा ओर गाई नदी सुबह भयंकर रूप में वेहे रही है। गगरा ओर डेमो नदी की बड़ती पानी में मुक्तियार , चिमनमुख और नामनी सिलासुती ग्राम पंचायत के अधीन 20 से अधिक गांव को प्रभावित किया। इनमेस दोनों नदियों ने अधिक नामनी सीलासुंती गाँव पंचायत के उत्तर सीलाबाली गाँव, पूर्व सीलाबाली गाँव, गौरांगपुर, भैयाम बेलगुड़ी, महारानी पुर और मुक्तियार गाँव पंचायत के भैरबपुर, काकबारी, सोनालीपुर, करेंगबस्ती, आशीघर-दसघर गांव को ज्यादा प्रभावित किया। सीमेननमुख, मुक्तियार और नामनी सीलासुती ग्राम पंचायतों के निवासियों के मुख सड़क जलमग्न होने की वजे से यातायात की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखित पंचायत के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं सरकार से मदद की मांग की है।

उफनती चिमेन नदी के बाढ़ ने उठा दिया रेलवे का पुल

पमुरकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वाले सभी सभी रेल रद्द

असम धेमाजी। असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से धेमाजी जिले में भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। शाम को करीब तीन बजे से चिमन नदी में पानी ओर ज्यादा बढ़ने लगी उफनती पानी ने नदी के उपर बनी रेलवे पुल के पश्चिम तट के एक खंभे से हटा दिया। पुल रेल लाइन के पट्टी के वेज के लटके हुए हैं। इसी दौरान रंगिया, डेकार गांव से सिलापथार होकर मुरकोंग सेलेक रेलवे स्टेशन तक जाने ओर आने वाले सभी रेलों के आवागम रद्द कर दी गई है।

नाबालिग से कराई जा रही थी हेरोइन की सप्लाई, 20 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया

दिल्ली। द्वारका जिला पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे नशे पर लगाम, देश को सलाम अभियान के तहत एक नाबालिग को 20 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। पुलिस ने नशीले पदार्थ की सप्लाई में इस्तेमाल की जा रही टीवीएस एन-टार्क स्कूटी भी जब्त की है। उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स सेल लगातार नशा तस्करों पर नजर रख रही थी। जांच के दौरान पता चला कि पुलिस की सख्ती के चलते हेरोइन सप्लायर संदेह से बचने के लिए नाबालिगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल फोन के माध्यम से हेरोइन की सप्लाई करा रहे हैं। सूचना के आधार पर शुक्रवार की रात विकासपुरी-उत्तम नगर नाला रोड स्थित फल मंडी के पास घेराबंदी की गई। वहां स्कूटी से हेरोइन की खेप पहुंचाने आए एक नाबालिग को पुलिस ने पकड़ लिया। उसकी तलाशी में 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस संबंध में उत्तम नगर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया है कि वह रणहौला क्षेत्र में रहने वाले एक कथित ड्रग तस्कर के निर्देश पर हेरोइन की सप्लाई करता था। उसे किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया गया।

बराक घाटी में हाईकोर्ट की स्थायी पीठ की मांग तेज, हाइलाकांडी में जिला समिति का गठन

● विधायक डॉ. मिलन दास ने स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग का किया समर्थन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: असम के बराक घाटी में गौहाटी हाईकोर्ट की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग को लेकर 28 जून रविवार को हाइलाकांडी के मैत्री भवन में एक महत्वपूर्ण नागरिक सभा आयोजित की गई। सभा में अधिवक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न वर्गों के 100 से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में हाइलाकांडी के विधायक डॉ. मिलन दास ने बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि यह क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से लंबित और न्यायोचित मांग है। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मांग को पूरा कराने के लिए वे हरसंभव प्रयास करेंगे। साथ ही आंदोलन से जुड़े संगठनों द्वारा जनजागरूकता और जनसमर्थन जुटाने की पहल की सराहना भी की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में बराक घाटी के लोगों को न्यायिक कार्यों के लिए गुवाहाटी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय, धन और संसाधनों की भारी हानि होती है। उनका कहना था कि स्थायी हाईकोर्ट पीठ की स्थापना से क्षेत्र के लोगों को न्याय तक आसान और समान पहुंच सुनिश्चित होगी। बैठक में सर्वसम्मति से हाईकोर्ट बेंच डिमांड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, हाइलाकांडी जिला का गठन किया गया। समिति के अध्यक्ष के रूप में मानव चक्रवर्ती को चुना गया, जबकि विभिन्न पदों पर अधिवक्ताओं और सामाजिक प्रतिनिधियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। निर्णय लिया गया कि समिति के तीन प्रतिनिधि 16 जुलाई को गौहाटी हाईकोर्ट में प्रस्तावित कार्यक्रम में भाग लेंगे। सभा के अंत में स्थायी हाईकोर्ट पीठ की मांग के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें करीब 300 नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन जताया। वक्ताओं ने कहा कि यह किसी क्षेत्रीय या राजनीतिक हित का मुद्दा नहीं, बल्कि संविधान के तहत सभी नागरिकों को न्याय तक समान और सुलभ पहुंच दिलाने की मांग है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की।

ड्रग्स तस्कर को बहन की शादी के लिए नहीं मिली अंतरिम जमानत

● दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ड्रग्स तस्कर को बहन की शादी में शामिल होने के लिए 20 दिन की अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपों की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और एनडीपीएस अधिनियम के सख्त प्रावधानों का हवाला दिया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। बिहार में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए मानवीय आधार पर 20 दिन की अंतरिम जमानत की आरोपित की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया। ड्रग्स की तस्करी और 40 किलो से ज्यादा मात्रा में गांजा रखने के आरोपित की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया की अवकाश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पर लगे आरोप की गंभीर हैं और उसके पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड व भारी मात्रा में बरामद किए गए ड्रग्स को देखते हुए उसे अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं बनता है। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि पुलिस ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 2024 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत हुई प्राथमिकी में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि आरोपित एक आदतन अपराधी है और उसे 40 किलो से ज्यादा गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपित के अन्य भाई भी हैं जो बहन की शादी में धार्मिक रस्में निभा सकते हैं। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत के नियम बहुत सख्त हैं और अंतरिम जमानत देने की शक्ति का इस्तेमाल अदालत विशेष स्थिति में ही कर सकती है। अदालत ने कहा कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा-37 के तहत पाबंदियां अनिवार्य हैं और ये जमानत देने से जुड़े सामान्य नियमों से ऊपर हैं। ऐसे में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामलों में अंतरिम या नियमित जमानत केवल बहुत विशेष और असाधारण हालात में ही दी जा सकती है। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता इस मामले में कोई असाधारण या ठोस वजह नहीं दिखा पाया और वह इस स्तर पर अंतरिम जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।